MR. SPEAKER : Now we will cover the whole of India ?

SHRI P. VISWAMBHARAN : The Minister has mentioned so many projects.

MR. SPEAKER : This question is not about any particular place. Let us go to the next question.

SHRI K. SURAYANARAYANA—*rose*—

MR. SPEAKER : You want to ask about Kothagudium ? We cannot cover the whole of India in this question. He may also resume his seat.

SHRI P. VISWAMBHARAN : The Minister has mentioned other projects. Why did not he mention this also? What is the position in regard to the proposed naphtha-based petro-chemical complex in Cochin ?

MR. SPEAKER : No, please. We cannot go from State to State.

श्री रवि राय : झा साहब के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने कुछ धीमी आवाज में कहा कि हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री को दिया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन कौन सज्जन हैं जो इस को चला रहे हैं?

श्री अशोक मेहता : काफी लोग उसके शेयर होल्डर होंगे लेकिन उसके चलाने वाली बिरला कम्पनी है, वह तो आप जानते हैं।

INCOME-TAX CASES

***554. SHRI PREM CHAND VERMA** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pending assessment of Income-tax cases have been progressively rising during the last six years;

(b) if so, what was the number of pending assessment cases in 1961 and what was the number at the end of 1967; and

(c) how long it would take to complete the back-log as a result of the steps taken to clear the pending assessment cases and collect the arrears ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of pending assessment cases as on 31st March, 1961 and 31st March, 1967 was 6,19,117 and 23,47,513 respectively.

(c) It is not possible to estimate the exact time it would take to clear the back-log of pending assessments and collect the arrears though all effective steps are being taken to do so as soon as possible.

श्री प्रेम चंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि 1961 के 6 लाख से ज्यादा केसेज बाकी हैं और 1967 से 23 लाख केसेज इनकम टैक्स के बाकी हैं, तो क्या यह दुरुस्त है कि इनकम टैक्स आफिसर्स मार्च महीने में जितने केसेज की असेसमेन्ट करते हैं वह सारे साल की असेसमेन्ट से एक-चौथाई हिस्सा होता है और यह एक-चौथाई हिस्सा वह इतनी हरी में करते हैं, इतनी जल्दी में केसेज करते हैं कि 50 प्रतिशत केसेज की अपीलें होती जिसकी वजह से यह सरकार का सारे का सारा रुपया, करोड़ों रुपया, उनसे मिल कर वसूल नहीं होने देते, वह वसूल नहीं होने देना चाहते न उस के लिए कुछ करते हैं, तो क्या सरकार को मालूम है कि यह सारी कार्यवाही पूंजीपति लोग उनसे मिल कर करते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमन् जल्दबाजी तो तभी होती है जबकि उस समय की सीमा तक हम पहुंच जाते हैं जब तक कि असेसमेन्ट कर सकते हैं। इसलिए कि कोई असेसमेन्ट से छूट न जाय, इसलिए जल्दी की जाती है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं इसी सिलसिले में कि जितना रुपया बाकी है इस

वक्त, क्या यह सच है कि उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा जो पैसा बाकी है जो कई करोड़ रुपये है वह जिस की तरफ यह बैलेंस है उन के टोटल के लगभग 10 परसेन्ट के ऊपर है, टोटल जिनके पास बाकाया है उनके 9. प्वाइंट कुछ यह हैं जिनके ऊपर 50 परसेंट से ज्यादा पैसा बकाया है, क्या यह सच है और क्या यह भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं? और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है?

श्री कृष्ण चन्द पन्त : यह बात 50 परसेन्ट की तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह बात सही है कि कई केसेज जो इसमें कलेक्शन के बड़े-बड़े हैं वह पैसे वालों के हैं और इसलिए हम ने यह किया है कि हायर इनकमकम्पनी केसेज के लिए और कम्पनी केसेज के लिए अलग से सर्किल्स बना दिए हैं ताकि इन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

SHRI S. S. KOTHARI : The current budget for the year 1968-69 provides the limitation period for completing assessments being reduced from four to two years. I think it is a very commendable move. Would the Ministry increase the strength of the department *i.e.* the number of income-tax officers and IACS in order to see that all assessments are completed within the new limitation period of two years ?

SHRI K. C. PANT : Naturally, the Ministry will take all consequential steps and where it is essential to increase the staff, it will also be done. In fact, certain steps have been taken recently.

श्रीमती लक्ष्मीबाई : मैं यह जानना चाहती हूं कि यह इनकम टैक्स वसूल करने वाले इंसपेक्टर जो होते हैं क्या सरकार को मालूम है कि बड़े-बड़े साहूकारों के यहां यह पार्ट-टाइम हिसाब किताब लिखने का काम करते हैं और उनसे मिले होते हैं इसलिए पैसा वसूल नहीं करते हैं? अगर सरकार को मालूम है तो उन इंसपेक्टरों के बारे में वह क्या कर रही है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि बहुत से लोग जिनके ऊपर बकाया होता है वह दिवाला निकाल कर बैठ जाते हैं, दिवालिया होने से वह उससे बरी हो जाते हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री कृष्ण चंद पंत : जहां तक पार्ट-टाइम काम करने का सवाल है सरकार को नहीं मालूम है कि इनकम टैक्स आफिसर पार्ट-टाइम काम करते हैं और अगर कोई दिवालिया हो जाय तो सरकार उसमें क्या कर सकती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी मंत्री महोदय ने जो लाखों की संख्या में केसेज की गिनती बतायी है कुल मिला कर के उसमें कितनी राशि है और बूथलिंगम कमेटी की जो रिपोर्ट आई है क्या उसके प्रकाश में कुछ ऐसे सरल उपाय निकाले जायेंगे जिस से कि यह राशि अधिक-से-अधिक प्राप्त हो सके ?

श्री कृष्ण चंद पंत : जी हां । इस वक्त जो 23 लाख केसेज के करीब हैं उस के लेटेस्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन कोई 400–500 करोड़ के बीच में कलेक्शन का एरियर है और बूथलिंगम ने जो सिफारिशें की हैं उन पर विचार किया जा रहा है। जो कोई सिफारिश उस में मदद देने वाली होगी उसको जरूर अपनाएंगे।

श्री शिव नारायण : मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि हर साल इस बात की शिकायत होती है कि जब मार्च का महीना आता है तो लोग बड़ा हरीअप करते हैं तो क्या सरकार इसका कोई मुनासिब इंतजाम आइन्दा के लिए करेगी कि तिमाही, छःमाही या नौ माही चेकिंग करके जिन पर यह रुपया बाकी हो उनसे वसूल किया जाय ? अभी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 5 सौ करोड़ रुपया बाकी है तो क्या सरकार उन से मिल कर कोई ऐसा कम्प्रोमाइज करेगी जिसमें एक-चौथाई उनको छोड़ दे और बाकी वह दे दें ?

श्री कृष्ण चंद पंत : यह दोनों सजेशन फार ऐक्शन हैं।

श्री मोहम्मद इस्माइल : जो यह केसेज चल रहे हैं जिन्होंने कि इनकम टैक्स नहीं दिए हैं क्या उसमें कोई केसेज ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बाई इंस्टालमेन्ट्स हम देने के लिए तैयार हैं अगर गवर्नमेन्ट यह इंस्टालमेन्ट मान ले? दूसरा इसी सिलसिले में यह मालूम हुआ है कि बर्ड एण्ड कम्पनी ने अपने मजदूरों को नोटिस दे दिया है यह कह कर कि गवर्नमेन्ट इंस्टालमेन्ट्स के लिए राजी नहीं है और इसलिए हम कारखाना बन्द कर रहे हैं, क्या इस तरह की अपील किसी ने की है या नहीं कि बाई इंस्टालमेन्ट हम देना चाहते हैं और गवर्नमेन्ट इसमें क्या करना चाहती है? खास तौर से बर्ड एण्ड कम्पनी बाई इंस्टालमेन्ट देने के लिए राजी है लेकिन गवर्नमेन्ट राजी नहीं है इसलिए वह अपना कारखाना बन्द करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : किसी खास कम्पनी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह अक्सर होता है कि अगर कोई असेसी आता है और कहता है कि वह इंस्टालमेन्ट में कर अदा कर देगा, दूसरी तरफ़ डिपार्टमेन्ट अगर यह समझे कि इंस्टालमेन्ट न करने से इस कर की अदायगी में नुकसान होगा, तो इंस्टालमेन्ट की इजाजत दे दी जाती है।

SHRI HEM BARUA : May I know whether it is a fact that an amount of Rs. 541.71 crores of assessed income-tax is outstanding from some 15 big individuals and 15 firms and whether it is also a fact that a foreign oil company, Burmah-Shell Refineries Limited, operating its business in India, has to pay an income-tax of Rs. 286 lakhs to the Government and they have not paid, and if so, what steps Government have taken mop up these tax arrears early from the individuals and firms concerned ?

SHRI K. C. PANT : This information has been given recently in answer to a question. While I cannot vouchsafe the accuracy of the figures, broadly speaking, the Burmah-Shell figures appear to be correct. The amount of about Rs. 540 crores refers to the entire collection arrears and not to 10 or 15 firms or individuals. A lot of these arrears are locked up in the various stages of the legal machinery. Wherever we can collect them, certainly we collect them.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, लाखों की तादाद में केसेज़ काफी लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं, ये केसेज़ जल्दी निपटें, क्या इसके लिये सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है, क्या कोई ऐसा तरीका निकालेगी जिससे हमको रकम जल्दी मिले और जो इंकम टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं वे भी अधिक दिन तक कोर्ट के चक्कर न काटें ?

श्री कृष्ण चंद पंत : कई कदम उठाये जा रहे हैं। कई बार इस पर बहस हो चुकी है और सदन के सामने वे कदम मैंने रखे हैं। अगर आप चाहेंगे और फिर मौका आयेगा तो फिर सारा ब्योरा आपके सामने रख दूंगा।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : May I know from the hon. Finance Minister whether the Government have got any proposal to award Bharat Ratna or Padma Vibhushan to the highest income-tax evaders and if so, what are the names in that list ?

MR. SPEAKER : This is the most important question !

SHORT NOTICE QUESTION

OLYMPIC GAMES IN MEXICO

+

SNQ. 6. SHRI CHANDRA JEET YADAV :
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :
SHRI H. N. MUKERJEE :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that International Olympic Committee has allowed South African Republic to take part in